(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

3517. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं/योजनाएं/जलाशय/बांध चालू किए हैं और किन-किन को आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है जहां निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है ;

(ग) किन-किन परियोजनाओं के काम में विलम्ब हो रहा है और इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) निर्माण-कार्य में विलम्ब होने से लागत में किस हद तक वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) सूचना अनुपत्र में दी गई है। (देखिए परिशिष्ट 161, अनुपत्र संख्या 81]

कृषि भूमि का कुल क्षेत्र

3518. **श्री राघवजी:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य में कुल कितने क्षेत्र में कृषि होती है और प्रत्येक राज्य में सरकारी साधनों से तथा निजी साधनों में सिंचाई सुविधा प्राप्त भू-क्षेत्र संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उन राज्यों में, जहां अपेक्षाकृत कम सिंचित भूमि है परन्तु जमीन उपजाऊ है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सूचना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) कुंओं की सिंचाई और लघु सिंचाई कार्यों को बढ़ावा देने के अतिरिक्त देश में सिंचाई सुविधाएं विकसित करने के लिए 263 वृहद सिंचाई परियोजनाएं तथा 1104 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गयी है। अब तक 83 वृहद और 777 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो गयी हैं।

विवरण]

31.3.91 की स्थिति (हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	आंकी गयी सिंचाई सुविधाएं (सृजित क्षमता)	
			सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश . .	16194	4865.41	1548.56
2.	अरूणाचल प्रदेश . .	301	59.28	0.05
3.	असम . . .	3229	618.66	174.87
4.	बिहार . . .	11195	4661.20	3904.80
5.	गोआ . . .	222	27.51	1.21
6.	गुजरात . . .	12336	1655.47	1446.12

1	2	3	3	5
7.	हरियाणा	3790	2776.06	1317.24
8.	हिमाचल प्रदेश	807	121.99	14.67
9.	जम्मू व काश्मीर	1049	508.44	7.65
10.	कर्नाटक	12879	2272.00	561.87
11.	केरल	2444	1083.79	109.08
12.	मध्य प्रदेश	22815	3490.74	1374.66
13.	महाराष्ट्र	21177	3165.55	1340.55
14.	मणिपुर	164	111.96	0.36
15.	मेघालय	1104	40.69	9.20
16.	मिजोरम	584	10.06	—
17.	नागालैण्ड	601	62.42	1.24
18.	उड़ीसा	8077	2464.19	571.23
19.	पंजाब	4279	3035.85	2905.74
20.	राजस्थान	25678	2650.82	1633.55
21.	सिक्किम	114	24.07	—
22.	तमिलनाडु	8426	2259.42	1125.99
23.	त्रिपुरा	312	73.36	18.45
24.	उत्तर प्रदेश	20817	10475.90	14714.10
25.	पश्चिम बंगाल	6117	2954.07	900.81
संघ राज्य क्षेत्र		232	49.91	56.68
	कुल	184943	49018.82	3788.68

Irrigation system in India

3519. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the World Bank's conclusion that wide-spread corruption is the root cause of the poor irrigation system in India;

(b) if so, Government's reaction thereto;

(c) the reasons for poor performance in the irrigation sector; and

(d) the steps being taken to enforce firm quality control and effective supervision at all stages of construction?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (c) Yes Sir. The Irrigation Sector Review Report of the World Bank refers to modest salary levels and inadequate performance related incentives of staff belonging to State Irrigation Departments in comparison to financial gains that are possible through collusion with contractors or illicit collection of revenues from farmers in exchange for water distribution favours. The report cities poor sector planning poor financial management inadequate water mangement and maintenance as the main causes of indifferent performance of the irrigation system.

(b) and (d) The observations of the World Bank have been brought to the knowledge of the State Governments. Steps being taken to improve quality of construction and supervision *inter-alia* include periodical site inspections during all phases of construction, Stress on data collection, compilation, analysis and